Head/Sub-Head of Development	Seventh Five-Year Plan (1985-90) Agreed Outlay
Irrigation & Flood Control	69600
Energy	78850
Industry & Minerals	14000
Transport	18725
Science, Technology & Environment	400
General Economic Services	3625
Education Sports, Art & Culture	17550
Health	5450
Water Supply	7000
Housing & Urban Development	4730
Other Social Services	4250
General Services	1600
GRAND TOTAL :	270000

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

590. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किस मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) इस मंत्रालय में, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार पर्याप्त हिन्दी पदों का सृजन न होने के कारण, जिसका प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अभी तक गठन नहीं हो पाया है । गठन के बाद ही बैठकों का आयोजन किया जायगा तथा गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित करने के प्रश्न के कार्यान्वयन पर विचार किया जायगा ।

(ख) इस मंत्रालय के अधीन कोई सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और संस्थाएं नहीं है । इस मंत्रालय के रोकड़ अनुभाग ने 1 अक्तूबर, 1987 से शत

प्रतिशत कार्य हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ग) इस मंत्रालय में, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

591. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध मे क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, सके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : कैलेंडर वर्ष 1987 के दौरान योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक दो बैठकें हुई है। मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों मे गैर-सरकारी व्यक्तियो को नामित नही किया जाता। लेकिन योजना मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति के किसी एक गैर-सरकारी सदस्य को चालू वर्ष में योजना आयोग और योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समितियो की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए हमेशा आमंत्रित किया जाता रहा है ।

(ख) इस समय, योजना मंत्रालय के किसी भी अनुभाग मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे नही किया जा रहा है, क्योंकि सभी कर्मचारियो द्वारा अभी हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त नही किया गया है । लेकिन मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के तीन अनुभागों अर्थात् सामान्य अनुभाग, स्थापना 1 अनुभाग और स्थापना-2 अनुभाग को 10-11-1986 से राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया, जिसके द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि इन अनुभागों के वे कर्मचारी, जिन्हे हिन्दी मे प्रवीणता प्राप्त है, कुछ विनिर्दिष्ट विषयो पर अपना सरकारी काम केवल हिन्दी में करेंगे ।

(ग) योजना मंत्रालय मे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के उपबन्धो का, कुल मिलाकर अनुपालन किया जा रहा है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

502. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे सभी स्तरो पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए, जाने के संबंध मे क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागो, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलो में हिन्दी को अब तक नही अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और